

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1631/2014/श्रीगंगानगर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त सी हनुमानगढ़

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स रामकुमार संतलाल, 74-नई धानमण्डी, श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.के. पारीक

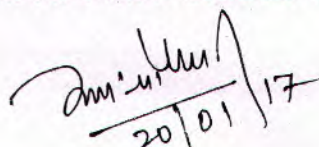
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 20.01.2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 85/आरवैट/श्रीगंगानगर/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.04.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 23, 24 सपठित नियम 19-ए के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 का वेट-10ए वार्षिक रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम के नियम 19-ए के तहत शास्ति रुपये 27,000/- एवं व्यापार बंद करने की सूचना देरी से प्रस्तुत करने के कारण शास्ति रुपये 300/- कुल मांग राशि रुपये 27,300/- आरोपित की गयी। उक्त आदेश दिनांक 11.04.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. राजस्व के अभिभाषक का कथन है कि व्यवहारी द्वारा वार्षिक रिटर्न टर्नओवर का समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति 100/- रुपये प्रतिदिन की दर से 27,000/-रुपये आरोपित की, जो कि नियमानुसार उचित है। साथ ही व्यवहारी द्वारा अपने प्रतिष्ठान के बंद होने की सूचना भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई नहीं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो शास्ति व्यवहारी पर आरोपित की गई है, वह उचित एवं विधिसम्मत है। किन्तु अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11.04.2014 को अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 25.02.2013 का पुनः बहाल किया जाये।


20/01/17

लगातार.....2.

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.04.2014 का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समक्ष अधिकारी ने प्रत्यर्थी को शास्ति आरोपण से पूर्व किसी प्रकार का विशिष्ट कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया, जो कि नियम 48 का उल्लंघन है क्योंकि नियम 48 में यह प्रावधान है कि किसी भी टैक्स को बढ़ाने, पेनल्टी आरोपण करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है, जो कि समक्ष अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 30.06.2010 को अपना व्यवसायी प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया और इस तिमाही का वेट-10 शून्य टर्नओवर व्यवसायी द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58(i) के तहत शास्ति रुपये 100/- प्रतिदिन के हिसाब से रुपये 27,000/- अधिकतम आरोपित किया जबकि प्रत्यर्थी के पास उक्त अवधि में कोई स्टॉक शेष नहीं बचा है तथा न ही कोई खरीद/बिक्री की गई है। अतः अपीलीय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अपास्त कर एक विधिसम्मत निर्णय पारित किया। अतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिसूचना क्रमांक 3011 [F.16(375)Tax/VAT/CCT/06-1614] दिनांक 20.01.2013 के अनुसार आलौच्य अवधि 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 थी। जबकि व्यवहारी द्वारा उक्त विवरण प्रपत्र 10A दिनांक 25.02.2013 को 270 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 की अवधि के विवरण पत्र वेट-10A, 270 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण उसके विरुद्ध कर निर्धारण आदेश 25.02.2013 द्वारा 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 27,000/- रुपये विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.04.2014 द्वारा उक्त 27,000/- रुपये की शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.04.2014 में यह निष्कर्ष दिया गया कि "आलौच्य अवधि में अपीलार्थी का टर्नओवर शून्य होने के कारण एवं पिछले वर्ष में अपीलार्थी के मासिक करदाता होने के कारण अपीलार्थी पर धारा 58(i) के तहत देय कर की 30 प्रतिशत से शास्ति देय बनती है। जबकि इस वर्ष में अपीलार्थी का टर्नओवर शून्य है तथा इसी स्थिति में अपीलार्थी पर देरी से रिटर्न प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित किया जाना कानून सम्मत नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रुपये 27,000/- अवधि होने के कारण अपास्त की जाती है।"

Amirul
20/01/17

6. विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम की धारा 21 तथा नियम 19 एवं नियम 19ए में निम्न प्रकार उपबंधित है:-

Sec. 21 FILLING OF RETURN -

- (i) *Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.*
- (ii) *Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.*
- (iii) *Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may be a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.*
7. नियम 19(1) से 19(10) तक विवरण प्रपत्र किन को किस प्रकार से पेश करने की स्थिति स्पष्ट की गयी है, जिसमें व्यवसायों के लिए त्रैमासिक व वार्षिक विवरण पत्र एवं किन व्यवसायों को केवल वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करना है, का उल्लेख किया गया है तथा विवरण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसमें से नियम 19(1) एवं 19(10) का यहा पर उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्न प्रकार है:-

Rule 19 (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10, VAT-10A and VAT-11, as the case may be.

Rule 19(10) :- *Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of due tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return.*

8. इस अधिनियम की धारा 58 **Penalty for failure to furnish return** से संबंधित थी जिसे Rajasthan Finance Act, 2011 द्वारा दिनांक 15.04.2011 को विलोपित कर दिया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT_Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए अधिसूचना क्रमांक 3011[F.16(375)Tax/VAT/CCT/06-1614] दिनांक 20.01.2013 के अनुसार वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 थी।

लगातार.....4.

Amish Kumar
20/01/17

अतः अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े (insertion) जाने के पश्चात् की अवधि के लिए विवरण प्रपत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे।

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की यह अपात्ति रही है कि विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नियम 48 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनना आज्ञापक है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया गया है, न कि शास्ति। विलम्ब शुल्क के आरोपण से पूर्व नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवहारी को कर निर्धारण से पूर्व नोटिस भी दिया गया था। अतः अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने की आपत्ति सारहीन है। अपीलार्थी की ओर से अपनी लिखित बहस में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते हैं।
10. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी का व्यापार दिनांक 30.06.2010 को बंद हो गया था तथा उसका पंजीयन दिनांक 01.07.2010 से निरस्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की त्रैमासिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत कर दी गई थी। लेकिन वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट 10A, 270 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी का टर्नओवर शुन्य था। किन्तु इस आधार पर व्यवहारी को वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट 10A प्रस्तुत करने से छुट प्रदान नहीं की जा सकती है तथा उसे विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क से छुट प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 58(i) के अधीन व्यवहारी पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरण प्रपत्र 10A प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये आरोपित शास्ति 27,000/- रुपये को अपास्त किया गया। जबकि धारा 58 दिनांक 15.04.2011 को विलोपित कर दिया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT_Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। आलौच्य अवधि 2010-11 के लिये वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 को धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी जबकि नियम 19A प्रभावी था।
12. आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। जिसके लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी को नियम 19A की पालना में विलम्ब शुल्क का भुगतान करना था। यह विलम्ब शुल्क विहित समयावधि के पश्चात् विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने या कर निर्धारण तक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने का

Ami Kumar
20/01/17

लगातार.....5:

पारिणामिक (Consequential) प्रभाव का परिणाम है। विलम्ब शुल्क स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। आलौच्य अवधि के पूर्व के वर्ष में प्रत्यर्थी व्यवहारी मासिक करदाता था। किन्तु आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 का टर्नओवर शुन्य होने से वह मासिक करदाता श्रेणी में नहीं आता है। अतः व्यवहारी के विरुद्ध नियम 19A के तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क आरोपित किया जाना न्यायसंगत है। आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब शुल्क के लिये नियम 19A के संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

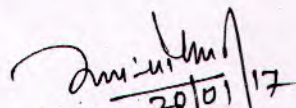
01-04-2012 to 31-03-2013 (sub. by the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment Rule) Rules 2012 (S.No. 2905 dated 30-03-2012) W.e.f. 01-04-2012

"19A Late Fee :- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

इस प्रकार जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि व्यवहारी मासिक करदाता नहीं है अतः नियम 19A के उक्त प्रावधान के अनुसार व्यवहारी के विरुद्ध 50/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम 5000/- रुपये तक विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत व्यवहारी के विरुद्ध विवरण प्रपत्र 10A को विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये आरोपित शास्ति 27,000/- रुपये को अपास्त करने में विधिक त्रुटि किये जाने से अपीलाधीन आलौच्य आदेश 11.04.2014 अपास्त किये जाने योग्य है।

13. अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.04.2014 को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.02.2013 में आंशिक संशोधन कर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 का वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A विलम्ब से प्रस्तुत करने के संदर्भ में व्यवहारी के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 के नियम 19A के अधीन 5,000/- रुपये विलम्ब शुल्क आरोपित किया जाता है।

14. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य